

# बिना एनओसी के चल रहीं फैक्ट्रियां

वर्ष 2008 से प्रदूषण बोर्ड ने नहीं दिया कोई लाइसेंस, सीएसई ने रिपोर्ट में किया खुलासा

● अमर उजाला ब्यूरो

कोटद्वार। जशोधरपुर की सभी फैक्ट्रियां वर्ष 2008 से बिना प्रदूषण बोर्ड की किसी एनओसी के चल रही हैं। प्रदूषण बोर्ड ने इन फैक्ट्रियों को संचालित करने के लिए कोई लाइसेंस ही नहीं दिया है। इसका खुलासा सीएसई की रिपोर्ट में किया गया है।

जशोधरपुर स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण संघर्ष समिति, सेंटर फार साइंस एंड इंवायरमेंट (सीएसई) और फैक्ट्री मालिकों की बैठक हुई। बैठक में सीएसई की ओर से वहां स्थित फैक्ट्रियों को लेकर किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट पेश की गई।

सीएसई की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यहां चल रही 17 फैक्ट्रियों को वर्ष 2008 से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से लाइसेंस नहीं दिया गया था। फिर भी यह 2008 से ही बिना किसी अनुमति के यहां पर संचालित हो रही हैं। यही नहीं जब भी यह फैक्ट्रियां प्रदूषण बोर्ड से एनओसी लेने गईं तो यह मानकों पर खरी नहीं उतर पाईं। इस कारण इनको एनओसी नहीं दी गई। अब

## आंदोलन के बाद शुरू हुई थी जांच

जशोधरपुर में ग्रामीणों ने फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण को लेकर नवंबर 2011 में आंदोलन शुरू किया था। लंबे आंदोलन के बाद प्रशासन के साथ समझौता हुआ था। इसके बाद यहां पर सीएसई ने फैक्ट्रियों की जांच शुरू कर दी थी।

## गैरकानूनी हैं यह फैक्ट्रियां

यह फैक्ट्रियां गैरकानूनी हैं। मानकों पर खरी नहीं उतरने के कारण इनको प्रदूषण बोर्ड से लाइसेंस नहीं दिया गया। यहां पर 17-18 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो इस तरह से चल रही हैं। - सुगंध जुनेजा, प्रोग्राम ऑफिसर सीएसई।

इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी उसके बाद ही अगली कार्रवाई होगी।

बैठक में सीएसई के अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2011 से पहले फैक्ट्रियों से निकलने वाला स्लैग इधर-उधर जमा किया जा रहा था। उसके बाद इसको नदी के किनारे डाल दिया जा रहा है। जो बारिश होते ही बह



कोटद्वार में फैक्ट्री मालिकों और अधिकारियों की बैठक में भाग लेते लोग।

जाता है और सीधे नदी में जाकर उसके पानी को दूषित करता है। इसका लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। कृषि जो पहले होती थी, उसकी मात्रा घट गई है। बैठक में सुगंध जुनेजा प्रोग्राम आफीसर सीएसई, चंद्र भूषण डिप्टी डायरेक्टर जर्नल सीएसई, डा. पीके जोशी सहायक वैज्ञानिक अधिकारी राज्य प्रदूषण

सिडकुल ने यहां पर नालियां और सड़कें नहीं बनाई हैं, जिस वजह से धूल उड़ने से प्रदूषण हो रहा है। लगभग हर फैक्ट्री में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी उपकरण लगे हैं। प्रदूषण विभाग में हर वर्ष हमारी फीस जाती है। उन्होंने कभी हमको यह नहीं बताया कि यहां क्या कमी है। प्रदूषण रोकने के लिए हम पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। - अनिल कंसल, अध्यक्ष उत्तरांचल स्टील मैनुफैक्चर एसोसिएशन।

बोर्ड, अमित पोखरियाल अवर फैक्ट्री मालिक और बड़ी संख्या में अभियंता राज्य प्रदूषण बोर्ड सहित ग्रामीण उपस्थित थे।